(i) Undertaking an overview of steps taken by different Ministries/ Departments for the review of laws and regulations;

(ii) Identifying proposals for amendment to laws and regulations having intersectoral impact.

(iii) Examining specific changes in existing rules and procedures in the case of selected economic and social sectors so as to make them transparent and predictable.

Recommendations of the said Commission have since been received and steps are being taken in consultation with the administrative Ministries/Departments for the amendment/repeal of irrelevant and Dysfunctional laws.

उत्तर प्रदेश के राजमार्गों के संबधं में लंबित प्रस्ताव

2302.**प्रो. रामबख्श सिंह वर्मा :** क्या जलभूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य में सड़क परियोजनाओं हेतु कोई प्रस्ताव अनुमोदन हेतु केन्द्रीय सरकार के पास भेजा है,

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(ग) प्रस्तावों को स्वीकार करने में विलम्ब के क्या कारण है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. देवेन्द्र प्रधान) : (क)से (ग) केन्द्र सरकार मुख्य रूप से केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है । राष्ट्रीय राजमार्गों को छोड़कर अन्य सड़कों के लिए अनिवार्य रूप से संबंधित राज्य सरकारें जिम्मेदार है । तथापि, केन्द्र सरकार, आर्थिक और अंतराष्ट्रीय महत्व की स्कीम तथा केन्द्रीय सड़क निधि के तहत राज्य सड़क परियोजनाओं की कतिपय श्रेणियों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है । राज्य सरकार से इन दो श्रेणियों के अंतर्गत पिछले कुछ समय में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

Closure of Indian Road Construction Corporation Ltd.

2303. SHRI JIBON ROY: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government has decided to close down Indian Road Construction Corporation Ltd. (IRCC); and

(b) if so, the reasons therefor and the details about alternative employment of workers and engineers of the IRCC?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (DR. DEBENDRA PRADHAN): (a) No. Sir.

(b) Does not arise.

Enquiry on land allotments at Kandla Port

2304. SHRI VIYALAR RAVI: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government have made any enquiry into the complaints of land allotment in Kandla Port in the last five years; and

(b) if so, what action has been taken on the complaint?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (DR. DEBENDRA PRADHAN): (a) and (b) Yes, Sir, Two cases that came to the notice of the Government are under investigation.

राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव पर खर्च की गयी धनराशि

2305. **श्री डी.पी. यादव :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: